अध्याय- XVIII : सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

18.1 त्रुटिपूर्ण योजना बनाने के कारण निष्फल व्यय

मंत्रालय ने आठ वे-इन-मोशन कम ऑटोमैटिक ट्रैफिक काउंटर कम क्लासीफॉयर्स की अधिप्राप्ति की (मार्च 2008) जबकि दो मशीने आठ वर्षों के विलम्ब के पश्चात् चालू की गई तथा शेष मशीने अभी तक अप्रतिस्थापित पड़ी थीं।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (मंत्रालय) ने, वाहनों के अतिभार पर नियंत्रण तथा इलैक्ट्रानिक डाटा के संग्रहण में सहायता करने के उद्देश्य से मंत्रालय के दिनांक 23 मार्च 2007 के खरीद आदेश द्वारा मैसर्स इंटरनेशनल रोड़ डायनामिक्स आई एनसी कनाडा (फर्म) से 462,659.00 सीएडी की लागत (₹2.16 लाख के परिवहन लागत सहित ₹1.89 करोड़) पर आठ वे-इन-मोशन कम ऑटोमैटिक ट्रैफिक आउंटर कम क्लासीफॉयर्स (डब्ल्यू आई एम कम एटीसीसी) की अधिप्राप्ति की। संविदा खरीद आदेश (मार्च 2007) की धारा 7(बी) के अनुसार यह माना गया था कि आठ प्रणालियो में प्रत्येक की बाधा रहित प्रचालन हेतु निष्पादन वारंटी विर्निर्माण डिजाइन त्रुटियों के प्रति अंतिम प्रणाली के चालू होने की तिथि से अट्ठाहरह कैलेण्डर माह या 1000 घंटे जो भी पहले हो, तक वैध होगी। संविदा की शर्तों के अनुसार फर्म को नवम्बर 2007 में कूल मूल्य का 70 प्रतिशत अर्थात् ₹1.30 करोड़ का प्रारंभिक भुगतान किया गया था। ये सिस्टम पांच राज्यों अर्थात् असम (01 नं.), छत्तीसगढ़ (01 नं.), गोवा (02 नं.), कर्नाटक (02 नं.), तथा राजस्थान (02 नं.) में लगाया जाना था। आपूर्तिकर्ता सिस्टम को प्रतिस्थापित तथा चालू करने के लिए तकनीकि सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार था। मंत्रालय ने (जुलाई 2007) संबंधित राज्यों के साथ उत्पाद की आवश्यक तकनीकी वर्णन तथा क्षमताओं के चर्चा की तथा उनसे स्थल की तैयारी हेतु उपयुक्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया। मार्च 2008 तक सभी सिस्टम प्राप्त हो गए थे और पदनामित परेषितियो को सौंप दिए गए थे। गोवा को

भेजे गए दो सिस्टम 13 मई 2009 के स्थानान्तरण आदेश द्वारा पश्चिम बंगाल को स्थानांतरित किए गए थे।

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि कर्नाटक में हस्सन तथा कोप्पाल में केवल दो सिस्टम जो जनवरी 2016 तक राज्य परिवहन निगम को सौंपे नही गए थे, प्रतिष्ठापित किए और चालू किए गए थे (जनवरी 2016)। शेष सिस्टम अभी तक प्रतिष्ठापित नहीं किए गए थे (दिसम्बर 2016)। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि प्रतापगढ़, राजस्थान में सिविल निर्माण कार्य पर ₹0.87 करोड़ का व्यय करने के पश्चात् सिस्टम तमिलनाडु में स्थानांतरित कर दिया गया था (सितम्बर 2014)। इस प्रकार, मंत्रालय की ओर से अदक्ष योजना बनाने तथा अप्रभावशाली मॉनीटरिंग करने के कारण अधिप्रापण की तिथि से आठ वर्ष बीत जाने के बाद भी छ: सिस्टम अभी तक प्रतिष्ठापित नहीं किए गए थे।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (दिसम्बर 2016) कि शेष सिस्टम के प्रतिष्ठापन तथा चालू करने का कार्य प्रगति पर था। प्रतापगढ़ (राजस्थान) में किए गए ₹0.87 करोड़ रू के निष्फल व्यय के संबंध में मंत्रालय ने बताया कि राजस्थान सरकार में डील कर रहे उनके परियोजना जोन से उत्तर प्राप्त होने के बाद ही अपना उत्तर भेजा जाएगा।

उत्तर ने दर्शाया है कि मंत्रालय की ओर से अदक्ष योजना बनाने तथा अभावशाली मॉनीटरिंग करने के कारण अधिप्रापण की तिथि से आठ वर्ष बीत जाने के बाद भी छ: सिस्टम अभी प्रतिष्ठापित किए जाने थे। इस प्रकार, जबकि धुरी भार का इलैक्ट्रानिक डाटा संग्रहण करने का उद्देश्य तथा अतिभार को रोकने का लक्ष्य पूरा नही किया जा सका, ₹1.85[1] करोड़ का व्यय भी निष्फल रहा।

---

[1] 8 मशीनों के लिए ₹1.89 करोड़ की लागत के प्रति, मंत्रालय ने ₹1.89 करोड़ का 70 प्रतिशत अर्थात ₹1.30 करोड़ जारी किए, 6 मशीनों के लिए कुल निष्फल व्यय - ₹0.98 करोड़ ((₹1.30 करोड़/8) * 6) भुगतान की राशि के बराबर है साथ ही प्रतापगढ़, राजस्थान में व्यर्थ व्यय - ₹0.87 करोड़ है।